

पंचवर्षीय योजना एवं औद्योगिक विकास

Dr. Panmal Pahariya

Associate Professor, Dept. of Geography, Govt. College, Tonk, Rajasthan, India

सार

पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। पंचवर्षीय योजनाएँ केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। इसे योजना आयोग (1951-2014) और नीति आयोग (2015) द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित की गई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था। पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री के साथ, आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता था, जिसका पद एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता था। मोटेक सिंह अहलूवालिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे (26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया)। बारहवीं योजना का कार्यकाल पूरा हो गया।^[1] चौथी योजना से पहले, राज्य संसाधनों का आवंटन पारदर्शी और उद्देश्य तंत्र के बजाय योजनाबद्ध पैटर्न पर आधारित था, जिसके कारण 1969 में गडगिल फॉर्मूला अपनाया गया था। आवंटन का निर्धारण करने के लिए तब से सूत्र के संशोधित संस्करणों का उपयोग किया गया है। राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता।^[2] 2014 में निर्वाचित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने योजना आयोग के विघटन की घोषणा की थी, और इसे नीति आयोग (अंग्रेज़ी में पूरा नाम "नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया" है) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

परिचय

पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया। अधिकांश कम्युनिस्ट राज्यों और कई पूंजीवादी देशों ने बाद में उन्हें अपनाया। चीन और भारत दोनों ही पंचवर्षीय योजनाओं का उपयोग करते हैं, हालांकि चीन ने 2006 से 2010 तक अपनी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का नाम बदल दिया। यह केंद्र सरकार के विकास के लिए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण को इंगित करने के लिए एक योजना (जिहुआ) के बजाय एक दिशानिर्देश (गुहुआ) था। भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की।^[3] प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास के शुभारंभ में इसकी एक बड़ी भूमिका थी। इस प्रकार, इसने कृषि उत्पादन का पुरजोर समर्थन किया और देश के औद्योगिकीकरण का भी शुभारंभ किया (लेकिन दूसरी योजना से कम, जिसने भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया)। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक महान भूमिका (एक उभरते कल्याण राज्य के साथ) के साथ-साथ एक बढ़ते निजी क्षेत्र (बॉम्बे योजना को प्रकाशित करने वालों के रूप में कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व) के लिए एक विशेष प्रणाली का निर्माण किया। प्रथम भारतीय प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। के.एन.राज^[4] के नेतृत्व में इसका प्रारूप तैयार किया गया था।

इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारीलाल नंदा उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य 'कृषि का विकास' था और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। आजादी के बाद देश का पुनर्निर्माण करना इस योजना का विजन था। एक अन्य मुख्य लक्ष्य देश में उद्योग, कृषि विकास की नींव रखना और लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा, कम कीमत में शिक्षा प्रदान करना था।^[5]

₹2,069 करोड़ (बाद में ₹2,378 करोड़) का कुल नियोजित बजट सात व्यापक क्षेत्रों: सिंचाई और ऊर्जा (27.2%), कृषि और सामुदायिक विकास (17.4%), परिवहन और संचार (24%), उद्योग (8.6%) के लिए आवंटित किया गया था।), सामाजिक सेवाएं (16.6%), भूमिहीन किसानों का पुनर्वास (4.1%), और अन्य क्षेत्रों और सेवाओं के लिए (2.5%)। इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सभी आर्थिक क्षेत्रों में राज्य की सक्रिय भूमिका थी। उस समय इस तरह की भूमिका उचित थी क्योंकि स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत बुनियादी समस्याओं का सामना कर रहा था-पूंजी की कमी और बचत करने की कम क्षमता।

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 8, August 2016

लक्ष्य वृद्धि दर 2.1% वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि थी; प्राप्त वृद्धि दर 3.6% थी, शुद्ध घरेलू उत्पाद 15% बढ़ गया। मानसून अच्छा था और अपेक्षाकृत उच्च फसल पैदावार, विनिमय भंडार और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, जिसमें 8% की वृद्धि हुई। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय से अधिक वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी बांध शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत सरकार के साथ मिलकर बच्चों के स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर को कम करने पर ध्यान दिया, अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया।

1956 में योजना अवधि के अंत में, पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना देश में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए वित्त पोषण की देखभाल और उपाय करने के लिए की गई थी। पांच इस्पात संयंत्रों को शुरू करने के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य में अस्तित्व में आए। सरकार ने विकास अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए योजना को सफल माना था। ये 1956 में समाप्त हुईं

दूसरी योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और "तेजी से औद्योगीकरण" पर केंद्रित थी। योजना ने 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद् प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल, महालनोबिस मॉडल का अनुसरण किया। योजना ने लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक विकास को अधिकतम करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश के इष्टतम आवंटन को निर्धारित करने का प्रयास किया। इसने संचालन अनुसंधान और अनुकूलन की प्रचलित अत्याधुनिक तकनीकों के साथ-साथ भारतीय सांख्यिकी संस्थान में विकसित सांख्यिकीय मॉडल के उपन्यास अनुप्रयोगों का उपयोग किया। योजना ने एक बंद अर्थव्यवस्था की कल्पना की जिसमें मुख्य व्यापारिक गतिविधि पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर केंद्रित होगी।^{[6][7]} दूसरी पंचवर्षीय योजना से, बुनियादी और पूंजीगत अच्छे उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में एक निर्धारित जोर दिया गया था।

भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और पांच स्टील प्लांट क्रमशः सोवियत संघ, ब्रिटेन (यूके) और पश्चिम जर्मनी की मदद से स्थापित किए गए थे। कोयले का उत्पादन बढ़ा। उत्तर पूर्व में अधिक रेलवे लाइनें जोड़ी गईं।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया को अनुसंधान संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया था। 1957 में, प्रतिभाशाली युवा छात्रों को परमाणु ऊर्जा में काम करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था।

भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आवंटित कुल राशि रु. 48 अरब। यह राशि विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित की गई थी: बिजली और सिंचाई, सामाजिक सेवाएं, संचार और परिवहन, और विविध। दूसरी योजना बढ़ती कीमतों की अवधि थी। देश को विदेशी मुद्रा संकट का भी सामना करना पड़ा। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को धीमा कर दिया।

लक्ष्य वृद्धि दर 4.5% थी और वास्तविक विकास दर 4.27% थी।^[8]

इस योजना की शास्त्रीय उदारवादी अर्थशास्त्री बी.आर. शेनॉय ने नोट किया कि योजना की "भारी औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए घाटे के वित्तपोषण पर निर्भरता परेशानी का एक नुस्खा था"। शेनॉय ने तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण एक युवा लोकतंत्र को कमजोर करेगा। 1957 में भारत को एक बाहरी भुगतान संकट का सामना करना पड़ा, जिसे शेनॉय के तर्क की पुष्टि के रूप में देखा जाता है।^[9]

तीसरी पंचवर्षीय योजना ने कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत-चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया। 1965-1966 में, भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। 1965 में भीषण सूखा पड़ा था। युद्ध ने मुद्रास्फीति को जन्म दिया और प्राथमिकता मूल्य स्थिरीकरण पर स्थानांतरित कर दी गई। बांधों का निर्माण जारी रहा। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाए गए थे। पंजाब ने बहुतायत में गेहूं का उत्पादन शुरू किया।

ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्राथमिक विद्यालय खोले गए। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाने के प्रयास में पंचायत चुनाव शुरू किए गए और राज्यों को विकास की अधिक जिम्मेदारियां दी गईं। भारत ने पहली बार आईएमएफ से उधारी का सहारा लिया। रुपये का मूल्य पहली बार 1966 में अवमूल्यन किया गया था।

राज्य बिजली बोर्ड और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को जिम्मेदार बनाया गया। राज्य सड़क परिवहन निगमों का गठन किया गया और स्थानीय सड़क निर्माण राज्य की जिम्मेदारी बन गया।

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 8, August 2016

लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% थी।^[8]

यह जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। तीसरी योजना की दयनीय विफलता के कारण सरकार को "योजना अवकाश" (1966 से 1967, 1967-68 और 1968-69 तक) घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच की अवधि के दौरान तीन वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। 1966-67 के दौरान फिर से सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई। कृषि, इसकी संबद्ध गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। भारत सरकार ने देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए "रुपये का अवमूल्यन" घोषित किया। चौथी पंचवर्षीय योजना ने धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पुरानी प्रवृत्ति को ठीक करने के उद्देश्य को अपनाया। यह स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति पर केंद्रित गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं।

इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों (इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया^[10]) और भारत में हरित क्रांति उन्नत कृषि। इसके अलावा, पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) की स्थिति 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के रूप में विकट होती जा रही थी और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध ने औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित धन लिया था।

- सबसे पहले बफर स्टॉक की अवधारणा पेश की गई और 50 लाख टन खाद्यान्न के बफर स्टॉक की परिकल्पना की गई
- सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) शुरू किया गया (1972-73)

लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 3.3% थी।^[8]

पांचवीं पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन (गरीबी हटाओ) और न्याय पर जोर दिया। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसने केंद्र सरकार को बिजली उत्पादन और पारेषण में प्रवेश करने में सक्षम बनाया।^[11]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई और बढ़ते यातायात को समायोजित करने के लिए कई सड़कों को चौड़ा किया गया। पर्यटन का भी विस्तार हुआ। बीस सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। इसका पालन 1975 से 1979 तक किया गया।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) के पहले वर्ष में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना है और इस प्रकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसे डी.पी.धर द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया है।

लक्ष्य वृद्धि दर 4.4% थी और वास्तविक विकास दर 4.8% थी।^[8] काम के बदले अनाज कार्यक्रम (1974-79) में प्रारंभ की गई थी।

विचार-विमर्श

जनता पार्टी सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना (1978-1980) पेश की। 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने इस योजना को फिर से खारिज कर दिया और एक नई छठी योजना बनाई गई। रोलिंग प्लान में तीन प्रकार की योजनाएं शामिल थीं जिन्हें प्रस्तावित किया गया था। पहली योजना वर्तमान वर्ष के लिए थी जिसमें वार्षिक बजट शामिल था और दूसरी निश्चित वर्षों की योजना थी, जो 3, 4 या 5 वर्ष हो सकती है। दूसरी योजना भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रही। तीसरी योजना लंबी अवधि के लिए यानी 10, 15 या 20 वर्षों के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना थी। इसलिए चल योजनाओं में योजना के प्रारंभ और समाप्ति की तारीखों का निर्धारण नहीं किया गया था। चल योजनाओं का मुख्य लाभ यह था कि वे लचीली थीं और देश की अर्थव्यवस्था में बदलती परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्य, अभ्यास, अनुमानों और आवंटन के उद्देश्य में संशोधन करके निश्चित पंचवर्षीय योजनाओं की कठोरता को दूर करने में सक्षम थीं। इस योजना का मुख्य नुकसान यह था कि यदि प्रत्येक वर्ष लक्ष्यों को संशोधित किया जाता है, तो पांच साल की अवधि में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है और यह एक जटिल योजना बन जाती है। इसके अलावा, लगातार संशोधनों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में स्थिरता की कमी हुई। छठी पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को चिह्नित किया। मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और राशन की दुकानें बंद कर दी गईं। इससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई और रहने की लागत में वृद्धि हुई।

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 8, August 2016

यह नेहरूवादी समाजवाद का अंत था। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन का भी विस्तार किया गया। चीन की सख्त और बाध्यकारी एक बच्चे की नीति के विपरीत, भारतीय नीति बल के खतरे पर निर्भर नहीं थी [उद्धरण वांछित]। भारत के अधिक समृद्ध क्षेत्रों ने कम समृद्ध क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेजी से परिवार नियोजन को अपनाया, जिनमें उच्च जन्म दर बनी रही। सैन्य पंचवर्षीय योजनाएँ इस योजना के बाद से योजना आयोग की योजनाओं के अनुरूप हो गईं।^[12]

छठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी। लक्ष्य वृद्धि दर 5.2% थी और वास्तविक वृद्धि दर 5.7% थी।^[8] सातवीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसमें राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे। योजना ने प्रौद्योगिकी के उन्नयन द्वारा उद्योगों के उत्पादकता स्तर में सुधार लाने पर जोर दिया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य "सामाजिक न्याय" के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था।

छठी पंचवर्षीय योजना के परिणाम के रूप में, कृषि में लगातार वृद्धि हुई, मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण और भुगतान के अनुकूल संतुलन ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवश्यकता पर निर्माण करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया था। आगे आर्थिक विकास। सातवीं योजना ने बड़े पैमाने पर समाजवाद और ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयास किया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख क्षेत्र थे: सामाजिक न्याय, कमजोरों के उत्पीड़न को दूर करना, आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, कृषि विकास, गरीबी-विरोधी कार्यक्रम, भोजन, वस्त्र और आश्रय की पूर्ण आपूर्ति, छोटे की उत्पादकता में वृद्धि- और बड़े पैमाने पर किसान, और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाना।

स्थिर विकास की दिशा में प्रयास करने की 15 साल की अवधि के आधार पर, सातवीं योजना 2000 तक आत्मनिर्भर विकास की पूर्वापेक्षाओं को प्राप्त करने पर केंद्रित थी। इस योजना में श्रम बल में 39 मिलियन लोगों की वृद्धि की उम्मीद थी और रोजगार के बढ़ने की उम्मीद थी। प्रति वर्ष 4% की दर से।

भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना के कुछ अपेक्षित परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- भुगतान संतुलन (अनुमान): निर्यात - ₹330 बिलियन (US\$4.1 बिलियन), आयात - (-) ₹540 बिलियन (US\$6.8 बिलियन), व्यापार संतुलन- (-) ₹210 बिलियन (US\$2.6 बिलियन)
- व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात (अनुमान): ₹606.53 बिलियन (US\$7.6 बिलियन)
- व्यापारिक वस्तुओं का आयात (अनुमान): ₹954.37 बिलियन (US\$12.0 बिलियन)
- भुगतान संतुलन के लिए अनुमान: निर्यात - ₹607 बिलियन (US\$7.6 बिलियन), आयात - (-) ₹954 बिलियन (US\$11.9 बिलियन), व्यापार संतुलन- (-) ₹347 बिलियन (US\$4.3 बिलियन)

सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत, भारत ने स्वैच्छिक एजेंसियों और आम जनता के बहुमूल्य योगदान के साथ देश में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था लाने का प्रयास किया।

लक्ष्य वृद्धि दर 5.0% थी और वास्तविक वृद्धि दर 6.01% थी।^[13] और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 3.7% थी।

केंद्र में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण 1990 में आठवीं योजना शुरू नहीं हो सकी और 1990-91 और 1991-92 के वर्षों को वार्षिक योजना के रूप में माना गया। आठवीं योजना अंततः 1992-1997 की अवधि के लिए तैयार की गई थी। 1989-91 भारत में आर्थिक अस्थिरता का दौर था और इसलिए कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी। 1990 और 1992 के बीच, केवल वार्षिक योजनाएँ थीं। 1991 में, भारत को विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) भंडार में संकट का सामना करना पड़ा, जिसके पास केवल 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भंडार बचा था। इस प्रकार, दबाव में, देश ने समाजवादी अर्थव्यवस्था में सुधार का जोखिम उठाया। पी.वी. नरसिम्हा राव भारत गणराज्य के नौवें प्रधान मंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख थे, और उन्होंने भारत के आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनों में से एक का नेतृत्व किया, एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कई घटनाओं की देखरेख की। उस समय डॉ. मनमोहन सिंह (बाद में भारत के प्रधान मंत्री) ने भारत के मुक्त बाजार सुधारों की शुरुआत की जिसने लगभग दिवालिया राष्ट्र को किनारे से वापस ला दिया। यह भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) की शुरुआत थी।

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 8, August 2016

उद्योगों का आधुनिकीकरण आठवीं योजना का एक प्रमुख आकर्षण था। इस योजना के तहत बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज को ठीक करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने का काम शुरू किया गया था। इस बीच, भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। प्रमुख उद्देश्यों में शामिल थे, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, संस्थागत भवन, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, पंचायती राज की भागीदारी, नगर पालिकाओं, गैर सरकारी संगठनों, विकेंद्रीकरण और लोगों की भागीदारी।

26.6% परिव्यय के साथ ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई।

लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी और वास्तविक विकास दर 6.8% थी।

प्रति वर्ष औसतन 5.6 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 23.2% के निवेश की आवश्यकता थी। वृद्धिशील पूंजी अनुपात 4.1 है। निवेश के लिए बचत घरेलू स्रोतों और विदेशी स्रोतों से आनी थी, जिसमें घरेलू बचत की दर सकल घरेलू उत्पादन का 21.6% और विदेशी बचत की सकल घरेलू उत्पादन का 1.6% थी।^[14]

परिणाम

नौवीं पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद आई। अटल बिहारी वाजपेयी नौवीं योजना के दौरान भारत के प्रधान मंत्री थे। नौवीं योजना में मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की अव्यक्त और अस्पष्टीकृत आर्थिक क्षमता का उपयोग करने का प्रयास किया गया था। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन को प्राप्त करने के प्रयास में देश के सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत समर्थन की पेशकश की। आठवीं पंचवर्षीय योजना के संतोषजनक कार्यान्वयन ने राज्यों की तीव्र विकास के पथ पर आगे बढ़ने की क्षमता भी सुनिश्चित की। नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयासों को भी देखा गया। इसके अलावा, नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आम जनता के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों के विकास में योगदान देखा गया। पर्याप्त संसाधनों के साथ निर्धारित समय के भीतर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नौवीं योजना के दौरान विशेष कार्य योजनाओं (एसएपी) के रूप में नए कार्यान्वयन उपाय विकसित किए गए थे। एसएपी ने सामाजिक बुनियादी ढांचे, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और जल नीति के क्षेत्रों को कवर किया।

बजट

नौवीं पंचवर्षीय योजना में कुल सार्वजनिक क्षेत्र की योजना परिव्यय ₹859,200 करोड़ (US\$110 बिलियन) था। नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में योजना व्यय के मामले में 48% और योजना परिव्यय के संदर्भ में 33% की वृद्धि देखी गई। कुल परिव्यय में केंद्र का हिस्सा लगभग 57% था जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह 43% था।

नौवीं पंचवर्षीय योजना देश के लोगों के लिए तीव्र आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों पर केंद्रित थी। इस योजना का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देते हुए देश में विकास को बढ़ाना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना में विकासोन्मुख नीतियों को देश में गरीबों के सुधार की दिशा में काम करने वाली नीतियों में सुधार के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के मिशन के साथ जोड़ने पर काफी महत्व दिया गया। नौवीं योजना का उद्देश्य उन ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना भी था जो अभी भी समाज में प्रचलित थीं।

उद्देश्यों

नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना और देश में आर्थिक विकास को बढ़ाना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना का गठन करने वाले अन्य पहलू थे:

- जनसंख्या नियंत्रण
- कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देकर रोजगार सृजित करना।
- गरीबी में कमी।
- गरीबों के लिए भोजन और पानी की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता।
- देश में सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों जैसे सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना।

**International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering,
Technology & Management (IJMRSETM)**

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 8, August 2016

- कृषि के मामले में आत्मनिर्भरता का विकास करना।
- स्थिर कीमतों की मदद से अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी।

रणनीतियाँ

- भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन और विकास।
- देश की अर्थव्यवस्था में चुनौतियों का सामना करने के लिए नई पहल और सुधारात्मक कदमों की शुरुआत।
- तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग।
- रोजगार बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी समर्थन का संयोजन।
- आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए निर्यात की उच्च दरों को बढ़ाना।
- बिजली, दूरसंचार, रेलवे आदि जैसी सेवाएं प्रदान करना।
- देश के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए विशेष योजनाएँ।
- विकास प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं/निकायों और नगर पालिकाओं की भागीदारी और भागीदारी।

प्रदर्शन

- नौवीं पंचवर्षीय योजना ने 6.5% के लक्ष्य के मुकाबले 5.4% की जीडीपी विकास दर हासिल की
- 4.2% के लक्ष्य के मुकाबले कृषि उद्योग 2.1% की दर से बढ़ा
- देश में औद्योगिक विकास 4.5% था जो 3% के लक्ष्य से अधिक था
- सेवा उद्योग की वृद्धि दर 7.8% थी।
- 6.7% की औसत वार्षिक वृद्धि दर पर पहुंच गया।

नौवीं पंचवर्षीय योजना देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नए उपायों को तैयार करने के लिए पिछली कमजोरियों को देखती है। हालाँकि, किसी भी देश की एक सुनियोजित अर्थव्यवस्था के लिए, उस राष्ट्र की सामान्य आबादी के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों की संयुक्त भागीदारी होनी चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक, निजी और सरकार के सभी स्तरों का एक संयुक्त प्रयास आवश्यक है।

लक्ष्य वृद्धि 7.1% थी और वास्तविक वृद्धि 6.8% थी।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य:

- प्रति वर्ष 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि प्राप्त करें।
- 2007 तक गरीबी दर में 5% की कमी।
- कम से कम श्रम शक्ति को जोड़ने के लिए लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार प्रदान करना।
- 2007 तक साक्षरता और मजदूरी दरों में लैंगिक अंतर में कम से कम 50% की कमी।
- 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया।
- लक्ष्य वृद्धि: 8.1% - हासिल की गई वृद्धि: 7.7%।
- दसवीं योजना से क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बजाय एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण का पालन करने की उम्मीद की गई थी।
- दसवें पांच वर्षों के लिए ₹43,825 करोड़ (US\$5.5 बिलियन) का व्यय।

कुल योजना परिव्यय में से, ₹921,291 करोड़ (US\$120 बिलियन) (57.9%) केंद्र सरकार के लिए था और ₹691,009 करोड़ (US\$87 बिलियन) (42.1%) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए था।

- यह प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के दौर में था।
- इसका उद्देश्य 2011-12 तक 18-23 वर्ष आयु वर्ग के उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करना है।

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 8, August 2016

- इसने दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, गैर-औपचारिक, दूरस्थ और आईटी शिक्षा संस्थानों के अभिसरण पर ध्यान केंद्रित किया।
- तीव्र और समावेशी विकास (गरीबी में कमी)।
- सामाजिक क्षेत्र और उसमें सेवा प्रदान करने पर जोर।
- शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण।
- लैंगिक असमानता में कमी।
- पर्यावरणीय स्थिरता।
- कृषि, उद्योग और सेवाओं में वृद्धि दर को क्रमशः 4%, 10% और 9% तक बढ़ाना।
- कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 कर दें।
- 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं।
- कृषि विकास दर को 4% तक बढ़ाएं।

निष्कर्ष

भारत सरकार की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 9% की वृद्धि दर हासिल करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने 27 दिसंबर 2012 को बारहवीं योजना के लिए 8% की वृद्धि दर को मंजूरी दी।^[15]

बिगड़ते वैश्विक हालात को देखते हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि अगले पांच साल में 9 फीसदी की औसत विकास दर हासिल करना संभव नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में योजना के अनुमोदन से अंतिम विकास लक्ष्य 8% निर्धारित किया गया है।

अहलूवालिया ने राज्य योजना बोर्डों और विभागों के एक सम्मेलन के इतर कहा, "[बारहवीं योजना में] औसतन 9% के बारे में सोचना संभव नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं 8 से 8.5 प्रतिशत के बीच संभव है।" पिछले साल स्वीकृत बारहवीं योजना के लिए संपर्क किए गए पेपर में 9% की वार्षिक औसत वृद्धि दर के बारे में बात की गई थी।

"जब मैं व्यवहार्य कहता हूं ... इसके लिए एक बड़े प्रयास की आवश्यकता होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो 8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का कोई ईश्वर प्रदत्त अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि पिछले वर्ष की तुलना में विश्व अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से खराब हुई है। ...12वीं योजना (2012-13) के पहले वर्ष में विकास दर 6.5 से 7 प्रतिशत है।"

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जल्द ही उन्हें आयोग के अन्य सदस्यों के साथ अपने विचारों को साझा करना चाहिए ताकि देश के एनडीसी के अनुमोदन के लिए अंतिम संख्या (आर्थिक विकास लक्ष्य) का चयन किया जा सके।

सरकार का इरादा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को 10% तक कम करने का है। अहलूवालिया ने कहा, "हमारा लक्ष्य योजना अवधि के दौरान स्थायी आधार पर गरीबी अनुमानों को सालाना 9% कम करना है।" इससे पहले, राज्य योजना बोर्डों और योजना विभागों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्यारहवीं योजना के दौरान गरीबी में गिरावट की दर दोगुनी हो गई। आयोग ने तेंदुलकर गरीबी रेखा का उपयोग करते हुए कहा था कि 2004-05 और 2009-10 के बीच पांच वर्षों में कमी की दर प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5% अंक थी, जो कि 1993-95 के बीच की अवधि की तुलना में दोगुनी थी। 2004-05।^[16] इस योजना का उद्देश्य सभी प्रकार की बाधाओं से बचने के लिए राष्ट्र की ढांचागत परियोजनाओं को बेहतर बनाना है। योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में ढांचागत विकास में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक के निजी निवेश को आकर्षित करना है, जो सरकार के सब्सिडी बोझ को 2 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत करना भी सुनिश्चित करेगा। सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद)। यूआईडी (विशिष्ट पहचान संख्या) योजना में सब्सिडी के नकद हस्तांतरण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे:

- गैर-कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना।
- स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करने के लिए।
- उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए।

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

(A Monthly, Peer Reviewed Online Journal)

Visit: www.ijmrsetm.com

Volume 3, Issue 8, August 2016

- 0-3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण को कम करना।
- सभी गांवों में बिजली पहुंचाना।
- यह सुनिश्चित करना कि 50% ग्रामीण आबादी को उचित पेयजल उपलब्ध हो।
- हरित क्षेत्र को हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर बढ़ाना।
- 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।

संदर्भ

1. योजना आयोग, भारत सरकार: पंचवर्षीय योजना Archived 2015-08-04 at the Wayback Machine. Planningcommission.nic.in.
2. ↑ योजना आयोग (24 February 1997). "राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के वितरण के लिए गडगिल फॉर्मूला पर एक पृष्ठभूमि नोट" (PDF). मूल (PDF) से 10 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 December 2014.
3. ↑ स्थिरता के विश्वकोश में सोनी पेलिसरी और सैम गेयाल की "पंचवर्षीय योजनाएं", खंड 7 पीपी 156-160
4. ↑ https://en.m.wikipedia.org/wiki/K._N._Raj
5. ↑ Swami, V.N. (2013). D.C.C. Bank Clerk Grade Examination (मराठी में). Latur, India: Vidyabharti Publication. पृष्ठ 12–13.
6. ↑ Jalal Alamgir, India's Open-Economy Policy: Globalism, Rivalry, Continuity (London and New York: Routledge 2008), Chapter 2.
7. ↑ Baldev Raj Nayar, Globalization And Nationalism: The Changing Balance of India's Economic Policy, 1950–2000 (New Delhi: Sage, 2001).
8. ↑ L. N. Dash (2000). World bank and economic development of India. APH Publishing. पृष्ठ 375. आईएसबीएन 81-7648-121-1.
9. ↑ "A short history of Indian economy 1947-2014: Tryst with destiny & other stories". Mint (अंग्रेज़ी में). 14 August 2014. अभिगमन तिथि 15 August 2014.
10. ↑ Banking Awareness. Arihant Publications (India) Ltd. 2015. पृष्ठ 20. आईएसबीएन 978-93-11124-66-7.
11. ↑ "Historical Background of Legislative Initiatives" (PDF). मूल (PDF) से 22 September 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2013-09-21.
12. ↑ "13th Five-Year Defence Plan – A Re-Run of the Past | Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses". Idsa.in. अभिगमन तिथि 1 March 2013.
13. ↑ "9th Five Year Plan (Vol-1)". मूल से 30 November 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 August 2013.
14. ↑ Agrawal, A N (1995). Indian Economy: Problems of development and planning. pune: Wishwa Prakashan. पृष्ठ 676.
15. ↑ "National Development Council approves 12th Five Year Plan". The Indian Express. 2012-12-27. अभिगमन तिथि 2013-07-10.
16. ↑ "Business Line : Industry & Economy / Economy : Plan panel may cut bac...". मूल से 4 February 2013 को पुरालेखित.
17. ↑ "13th Five-Year Defence Plan– A Re-Run of the Past | Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses". मूल से 5 October 2015 को पुरालेखित.